ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

J&K Did It!!!!!

J&K qualified for the knockout in 2001-2002 and again making it to the knockout after a gap of 12 years showed that the J&K boys have grit and determination to come up in domestic cricket

'Assi'

The Mime Artist Who Spoke Through Silence in a World at War

'अमेरिका का शत्रु होना खतरनाक पर, अमेरिका से दोस्ती घातक है'

हैनरी किसिंजर की यह सीख न मानना बहुत भारी पड़ रहा है, अमेरिका के वैस्ट एशिया के मित्र देशों को

- नोबल पुरस्कार विजेता,अमेरिकी इकॉनमिस्ट जैफरी साक्स के अनुसार ट्रंप भ्रम के शिकार हैं, अतः उन्हें रोकना जरुरी है, इसके पहले कि, वे ग्लोबल इकॉनमी को खण्डहर की स्थिति में पहुंचा दें, तथा विश्व के सभी क्षेत्र इकोनॉमिक ''स्लो डाउन'' से ग्रस्त हो जायें।
- जैफरी साक्स को आशंका है, कि विश्व में ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर जायेगी।
- ईरान का स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ पर तो आधिपत्य है ही, तथा ईरान द्वारा उन खाड़ी देशों पर लगातार बमबारी जारी रखना, जो अमेरिका के सहयोगी व मित्र हैं, से इस क्षेत्र की ऑयल प्रोड्यूसिंग सुविधाएं और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं नष्ट करने के परिणाम वर्षों तक महसूस किये जायेंगे।
- सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी, कतर की गैस फील्ड्स को बंद करना पड़ा है, ईरान के ड्रोन-आक्रमणों के कारण। एक ऑयल फील्ड को बंद करना एक बहुत महंगी प्रक्रिया है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। बीसवीं सदी की कूटनीति के महान ज्ञाता हैनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, ''अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा है।'' वर्षों पहले कही गई इस बात की सच्चाई अमेरिका के पश्चिम एशियाई साथी अब सीख रहे हैं, जिसका उन्हें बहुत नुकसान और कष्ट उठाना पड़ रहा है।

कुछ विशेषज्ञ युद्ध को तुरंत समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जो ब्रिक्स देशों के एक साथ आने से ही संभव है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स ने कहा कि चीन, रूस, भारत और यूरोपीय संघ जैसे देशों द्वारा युद्ध रोकने की संयुक्त आवाज़, तथा अमेरिकी आक्रामकता को तुरंत रोकने की मांग, रुख में बदलाव ला सकती है और युद्ध रुक सकता है।

बदलाव के कुछ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव ने भारत में ईरानी दूतावास में शोक-पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर ईरान के प्रति एकजुटता दिखाई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बात की और तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा की।

सैक्स का मानना है कि डॉनल्ड ट्रंप भ्रमित हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध जारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजरबैजान ने ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया

तेल अवीव/तेहरान, 05 मार्च। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर उसके नखचिवान क्षेत्र पर ड्रोन हमला किए जाने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक ड्रोन नखचिवान के हवाई अड्डे के पास और दूसरा एक स्कूल के पास गिरा।

राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने कहा कि इस घटना पर ईरान को माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

इस घटना में एयरपोर्ट टर्मिनल को

- ईरान ने कहा उसने अजरबैजान की ओर कोई ड्रोन नहीं दागा।

नुकसान पहुंचा और दो नागरिक घायल हो गए। राष्ट्रपति अलीयेव ने इस घटना को 'कायराना हमला' बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ईरान ने इस ड्रोन हमले में हाथ होने से इनकार किया है और कहा है कि इस घटना की जांच की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने अजरबैजानी समकक्ष से फोन पर बातचीत में कहा कि तेहरान ने अजरबैजान की ओर कोई ड्रोन या अन्य प्रोजेक्टाइल नहीं दागा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हमलों के पीछे इजराइल की भूमिका हो सकती है, जिसका उद्देश्य ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध खराब करना है।

खामनेई की हत्या के छः दिन बाद भारत ने संवेदना व्यक्त की

लेकिन विलम्ब से संवेदना व्यक्त करना एक क्षतिपूर्ति करने की कोशिश जैसा निर्णय माना जा रहा है।

- अंततोगत्वा भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी द्वारा संवेदना व्यक्त करने का निर्णय लेने का कारण यह था कि शायद खामनेई की अमेरिका बमबारी से हुई मृत्यु पर भारत द्वारा चुप्पी बनाये रखना, ग्लोबल साऊथ और कुछ यूरोपीय देशों को बहुत अखरा था

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 05 मार्च। देर से ही सही, लेकिन भारत ने आज ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त किया। उन्हें तेहरान में इज़राइली मिसाइल हमले में मारे जाने के छह दिन बाद संवेदना प्रकट की गई।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत सरकार की ओर से ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास में जाकर शोक-पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए।

28 फरवरी को तेहरान में उनके आधिकारिक निवास पर हुए संयुक्त अमेरिका-इज़राइल हमले खामेनेई मारे गये थे। उनकी मृत्यु के बाद दूतावास ने शोक-पुस्तिका खोली, जहां राजनयिकों और अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित मिशन में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली भी मिसरी के दूतावास दौरे के दौरान मौजूद थे। खामेनेई की मृत्यु पर फतहाली ने कहा, हमने एक महान व्यक्तित्व खो दिया है-वह हमारे नेता, हमारे पिता थे। वह महान हस्ती हमेशा हमें इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने की पूरी कोशिश करने की सलाह देती थी। मेरा मानना है कि वे इतिहास के सही पक्ष में खड़े रहे और उन्हें उसका प्रतिफल मिला।

अमेरिका-इज़राइल बनाम ईरान संघर्ष पर फतहाली ने कहा हम उनकी मंशा जानते हुए भी बातचीत की मेज पर आए, और उन्होंने समय तय किया और लेकिन उससे पहले ही हमला कर दिया। हमने घोषणा की कि हम इसका जवाब देंगे। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र ने पहले ही बहुत समस्याओं का सामना किया है और यहूदी शासन हमारे क्षेत्र की सभी संपत्तियों को अस्थिर और नष्ट करना चाहता है।''

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, विदेश सचिव के माध्यम से औपचारिक शोक व्यक्त करने का निर्णय व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया। यह महसूस किया गया कि अमेरिका - समर्थित इज़राइली हमले पर प्रतिक्रिया न देने का पूर्व निर्णय वैश्विक दक्षिण के देशों और यूरोप के कुछ देशों में अच्छा नहीं माना जा रहा था और इससे वैश्विक जनमत भी भारत से दूर हो रहा था।

एक पूर्व आईएफएस अधिकारी, जो कई महत्वपूर्ण देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, ने कहा, यह नुकसान की भरपाई करने की कोशिश अधिक है, लेकिन दुर्भाग्य से नई दिल्ली को यहूदी खेमे का हिस्सा और अमेरिका-इज़राइल धुरी का अनुगामी माना जा रहा है।

बुलैट ट्रेन प्रोजैक्ट की लागत 83 प्रतिशत तक बढ़ी

मुम्बई और अहमदाबाद के बीच बन रहे इस प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए 90,000 करोड़ रु. की और आवश्यकता है

- पूर्व में इस प्रोजैक्ट की लागत एक लाख 800 करोड़ रु. आंकी गई थी और इसका 81 प्रतिशत खर्च जापान बतौर कर्ज दे रहा था पर रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग अनुबंधों पर भारत की असहमति के बाद जापान ने और कर्ज देने से इन्कार कर दिया।
- खबरों के अनुसार, प्रोजैक्ट की लागत बढ़कर 1,98,000 करोड़ रु. हो गई है और यह बढ़ी हुई लागत रेल विभाग, केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को वहन करनी होगी।

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 मार्च। भारत की पहली हाई-स्पीड रेल लाइन (बुलेट ट्रेन), मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर), की परियोजना लागत में 83 प्रतिशत की भारी वृद्धि होना बताया जा रहा है। इस लाइन के निर्माण के लिए अब लगभग 90,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

जापान ने मूल अनुमानित लागत 1,08,000 करोड़ रुपये में से लगभग 81 प्रतिशत राशि ऑफिशियल डवलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) ऋण के रूप में देने की सहमति दी थी। लेकिन रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग अनुबंधों को लेकर भारत और जापान के बीच मतभेद के कारण, टोक्यो में नई सनाई ताकाइची सरकार द्वारा इस पहले से ही विलंबित परियोजना के लिए अतिरिक्त ऋण देने की संभावना कम मानी जा रही है।

रिपोर्टों के अनुसार, अब परियोजना की लागत बढ़कर 1,98,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि अतिरिक्त राशि भारत सरकार के समेकित कोष (कन्सॉलिडेटेड) द्वारा वहन की जाएगी। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा (एनएचएसआरसीएल) की अपनी वित्तीय संरचना है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें शामिल हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बढ़ी हुई पूरी लागत का बोझ भारतीय रेल पर डाला जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, संशोधित लागत पर एक नोट जल्द ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिहार में जनादेश के साथ धोखा'

नई दिल्ली, 05 मार्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की पुष्टि करने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इसे बिहार में नेतृत्व तख्तापलट करार दिया है। साथ ही बिहार

- कांग्रेस ने नीतीश को राज्यसभा में भेजे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि बिहार में नेतृत्व का तख्तापलट हुआ है।

के जनादेश के साथ विश्वासघात बताया है। कांग्रेस सांसदजयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस जो बात कह रही थी, वह अब सच साबित हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जी2 ने मिलकर सत्ता में बदलाव और तख्तापलट किया है। उनके अनुसार, यह कई मायनों में लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात है।

महाराष्ट्र में शरद पवार कैसे बने विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार

पवार की बेटी ने न केवल इस रणनीति की रचना की बल्कि उस पर सफलता से अमल भी किया

- सूत्रों ने बताया कि पवार ने अंतिम क्षणों में राज्यसभा में पुनः जाने की इच्छा जताई, तो सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें विपक्ष का सर्वसम्मत प्रत्याशी बनाने की, क्योंकि तभी वे जीत सकते थे।
- इस चुनौती को साधने की कमान संभाली उनकी पुत्री सुप्रिया सुले ने। पहले वे उद्धव ठाकरे से मिली और पवार के लिए समर्थन मांगा। ज्ञातव्य है कि ठाकरे इस बार सीट पर दावा कर रहे थे और उद्धव के पुत्र आदित्य ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया था कि पहले शरद पवार को समर्थन दे चुके हैं अब उनकी बारी है, लेकिन अंततः उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को समर्थन देने की बात मान ली। यह सुप्रिया की पहली रणनीतिक सफलता थी।
- इसके बाद सुप्रिया ने महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं को साधा और अंततः कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व ने भी शरद पवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी, पर एक शर्त के साथ कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय नहीं होगा और शरद पवार एनडीए में नहीं जाएंगे। इस सम्बंध में आश्वासन मिलने के बाद शरद पवार की उम्मीदवारी पक्की हो गई।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) ने राज्य में मिलने वाली एकमात्र संभावित राज्यसभा सीट को लेकर होने वाला विवाद टाल दिया है।

शरद पवार ने आखिरी समय में अपने पहले के फैसले से यू-टर्न लेते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और उन्हें विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिव सेना (यू.बी.टी.), जो यह सीट अपने किसी नेता को देना चाहती थी, ने अपना दावा वापस ले लिया।

इस संयुक्त मोर्चे की मुख्य रणनीतिकार पवार की बेटी सुप्रिया सुले थीं, जिन्होंने कांग्रेस से संपर्क करने की पहल की।

सूत्रों के अनुसार, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की ओर से सुले ने पूरे दिन महाराष्ट्र, कांग्रेस नेताओं से बातचीत की।

सबसे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे से मिलकर पवार के समर्थन की मांग की, क्योंकि शिवसेना (यू.बी.टी.) ही इस सीट पर नजर रखे हुए थी।

ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा था कि चूँकि उन्होंने पहले एक सीट शरद पवार के लिए छोड़ी थी, इसलिए अब एहसान लौटाने का समय है।

सूत्रों ने बताया कि पासा तब पलटा, जब महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में फोन कर खड़गे और राहुल गांधी से परामर्श किया।

कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने शरद पवार की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। उनका मानना था कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के लिए उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है। सूत्रों का कहना है कि 85 वर्षीय पवार आने वाले दिनों में मुख्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के राज्यपाल बदले

नई दिल्ली, 05 मार्च। बिहार-महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दिल्ली के लैफ्टिनैट गवर्नर (उप राज्यपाल) भी बदल गए

- सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पश्चिम बंगाल में हुआ जहां राज्यपाल सी वी आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को नया राज्यपाल बनाया गया है।

हैं।दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान के आकाश पर अमेरिका के विमान ही विमान नज़र आते हैं

ये सभी विमान गत दो -तीन दशकों में लगातार भारत को ऑफर किए गए थे, पर भारत ने एक भी अमेरिकी फाइटर विमान का ऑर्डर नहीं दिया, आज तक

- कारण, हरदम की तरह टैक्नोलॉजिकल कारण बताता आया है भारत। पर क्या अमेरिकी फाइटर हवाई जहाज न खरीदने का कारण, शुद्ध टैक्नोलॉजी है या कुछ और भी।
- शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक बड़ा निर्णय लिया, पाकिस्तान को हथियार व फाइटर प्लेन सप्लाई करने का और पाकिस्तान ने बड़ा इठला-इठला कर, इन विमानों का भारत के खिलाफ जमकर उपयोग किया।
- भारत ने भी अपनी विमान व हथियार खरीदने की नीति निर्धारित की, और अपनी वायुसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुस की ओर देखा।
- शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, दोनों तरफ से भारी कोशिश हुई, भारत व अमेरिका को नज़दीक लाने के लिये, पर फिर मई 1998 में भारत ने न्युक्लियर बम बनाने की दृष्टि से, टैस्टिंग आरंभ की। अमेरिका ने बेरहमी से भारत पर दण्डात्मक प्रतिबंध लगाये।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 मार्च। आजकल ईरान के आसमान पर एक नजर डालिए जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोतों के डेक से उड़ान भरते अमेरिकी एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट, खाड़ी के ठिकानों से उड़ते एफ/ए-15 स्ट्राइक ईगल, लगातार कॉम्बैट एयर डिफेंस मिशन पर तैनात एफ-16, इज़राइल से अपनी पहली युद्ध तैनाती पर गए एफ-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर, रात में बिना रुके उड़ान भरते बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर, और कई स्तरों वाली वायु रक्षा को पार करते एफ-35ई दिखे, जिनमें से एक ने हाल ही में अपनी पहली एयर-टू-एयर जीत भी दर्ज की।

यह अमेरिकी लड़ाकू वायुशक्ति का सबसे बड़ा जमावड़ा है-युद्ध के दौरान होने वाली एक तरह की पूरी अभ्यास प्रस्तुति, जो दिखाती है कि जब अमेरिका पूरी ताकत से उतरता है तो उसकी वायुसेना और नौसेना क्या कर सकती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इन आसमानों में दिखाई देने वाले लगभग हर लड़ाकू विमान को पिछले 20 वर्षों में कभी-न-कभी भारत को भी बेचने के लिए पेश किया गया था। और भारत ने हर बार उन्हें खरीदने से मना कर दिया था।

यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपको मिसाइलों, स्टेल्थ जेटों और अरबों डॉलर के रक्षा संबंधों से पहले के दौर में जाना होगा-शीत युद्ध के समय में, जब अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसे भारत आज तक नहीं भूला है।

शीत युद्ध के दौरान वॉशिंगटन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, सिर्फ राइफल और टैंक ही नहीं, बल्कि अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान भी, जैसे एफ-86 सेबर, एफ-104 स्टारफाइटर, एफ-86डी, एफ-37 और बाद में बेहद अहम एफ-16 फाइटिंग फाल्कन, जो दुनिया के सबसे सक्षम बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमानों में से एक है। पाकिस्तान ने इन जेटों को उड़ाया, इनके साथ युद्ध लड़े, और इन्हें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लद्दाख के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया

लेह, 05 मार्च। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस अचानक त्यागपत्र से प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया

- दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है।

है, जब कुछ ही देर पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इस्तीफा दिया था।

कविंदर गुप्ता के इस्तीफे की खबर ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फैसले के पीछे के कारणों को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, उपराज्यपाल के पद छोड़ने का वास्तविक कारण अभी तक सार्वजनिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)